Government of Bihar
Department of Environment and Forests

ACT CCIP
ACTION ON CLIMATE TODAY

PRESS RELEASE

प्रकाशनार्थ

पटना, 25 जून 2018. माननीय केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, बिहार के उप-मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी और छत्तीसगढ़ के पर्यावरण एवं वन मंत्री श्री महेश गागदा द्वारा दो-दिवसीय पूर्वी भारत जलवायु परिवर्तन कनक्लेव के उद्घाटन के बाद कनक्लेव में दूसरे दिन जलवायु-प्रतिरोधक्षमता संपन्न कृषि, जल और वित्त पर तीन समर्पित तकनीकी सत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

कल आरंभ हुए कनक्लेव का आयोजन बिहार सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा यूके के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआइडी) के तहत कार्यरत ऍक्शन ऑन क्लाइमेट टूडे (ऍक्ट) और पटना स्थित एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (आद्री) के तहत कार्यरत सेंटर ऑफ एनवायरनमेंट, एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज (सीईईसीसी) के साथ मिलकर किया गया। कनक्लेव में भारत के पूर्वी क्षेत्र के नीति निर्माता, सरकारी उच्चाधिकारी, निर्णयकर्ता और उद्योगपति तथा वैश्विक, राष्ट्रीय, उपराष्ट्रीय और गैर-सरकारी विशेषज्ञ विचार-विमर्श करने तथा जलवायु के मामले में प्रतिरोधक्षमता-संपन्न राष्ट्र के निर्माण पर सबकों का आदान-प्रदान करने के लिए एक साथ शामिल हुए।

जलवायु-प्रतिरोधक्षमता संपन्न कृषि, जल और वित्त पर आयोजित हर सत्र में एक-एक थीम आधारित रिपोर्ट भी जारी की गई - 'बिहार में जलवायु-प्रतिरोधक्षमता संपन्न फसलों की मूल्यशृंखला का मूल्यांकन', 'हरित कौशल विकास कार्यक्रम (जीएसडीपी) : जल संबंधी बजट निर्माण और अंकेक्षण' तथा ' उड़ीसा में जलवायु परिवर्तन संबंधी बजट की कोडिंग'।

ऍक्शन ऑन क्लाइमेट टूडे और क्लाइमेट चेंज इन्नोवेशन प्रोग्राम (ऍक्ट-सीसीआइपी) द्वारा तैयार किए गए 'बिहार में जलवायु-प्रतिरोधक्षमता संपन्न फसलों की मूल्य शृंखला का मूल्यांकन' में मक्का, धान और मसूर को बिहार में जलवायु-प्रतिरोधशक्ति संपन्न तीन फसलों के रूप में चिन्हित किया गया है और मूल्यशृंखला दृष्टिकोण का उपयोग करके इन चिन्हित फसलों के लिए पूरे विस्तार से अवसरों का मूल्यांकन किया गया है।

वहीं, **पूर्वी भारत जलवायु परिवर्तन कनक्लेव 2018 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जिस महत्वाकांक्षी कौशल विकास कार्यक्रम- पानी संबंधी बजट निर्माण और अंकेक्षण पर हरित कौशल विकास कार्यक्रम (जीएसडीपी) -का शुभारंभ किया जा रहा है** उसे आद्री के तहत कार्यरत सेंटर फॉर एनवायरनमेंट, एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज (सीईईसीसी) द्वारा विकसित किया गया है।

उड़ीसा सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा तैयार रिपोर्ट तथा ऍक्ट-सीसीआइपी का लक्ष्य राज्य सरकार के योजना निर्माताओं को वर्तमान जलवायु परिवर्तन की प्रासंगिकता और उड़ीसा की जलवायु परिवर्तन विषयक राज्य कार्ययोजना में रेखांकित क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यय की संवेदनशीलता के संबंध में विस्तृत बजट कोडिंग अभ्यास के जरिए जानकारी देना है।

दो-दिवसीय कनक्लेव में उभरे मुख्य बिंदुओं में जलवायु-प्रतिरोधक्षमता संपन्न भारत के निर्माण पर संकल्पों का पालन करना, परस्पर सहयोग करना और सामूहिक कार्रवाई करना शामिल है। विद्वानों ने परियोजनाओं को जलवायु-रोधी बनाने के लिए विभागों द्वारा मिलकर काम करने, जलवायु-प्रतिरोध की परियोजनाओं में कार्पोरेट सोशल फंडिंग की रकम का उपयोग करने, जल प्रबंधन के बेहतर योजनाएं बनाने तथा अधिक आक्रामक कार्रवाइयां करने जैसे अनेक नीतिगत परिवर्तनों के सुझाव दिए।

कनक्लेव में पूर्वी भारत के राज्यों में अनुकूलन क्षमता के निर्माण के तरीकों पर और योजना तथा नीति निर्माण की प्रक्रिया में जलवायु परिवर्तन को मुख्य धारा में लाने के लिए राज्यों के बीच विचारों के आदान-प्रदान के संभावित अवसरों को चिन्हित करने पर सफलतापूर्वक चर्चा हुई। कनक्लेव में पूर्वी भारत ही नहीं, पूरे देश से तथा महत्वपूर्ण वैश्विक संगठनों के 100 से भी अधिक विशेषज्ञों, नेतृत्वकारियों और अमलकारों की भागीदारी हुई।

अबिनाश मोहंती,
निदेशक
सीईईसीसी, आद्री
मोबा. +91 9776478313